

इससे पहले: एम. आर. अग्निहोत्री और वी. के. बाली, जे.

समिति का प्रबंधन, गोस्वामी गणेश दत्त शांताराम कॉलेज, सेक्टर 32-सी, चंडीगढ़
राष्ट्रपति पंडित मोहन लाल के माध्यम से, -याचिकाकर्ता।

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ अपने प्रशासक और अन्य लोगों द्वारा से-उत्तरदाता।

1991 का सी. डब्ल्यू. पी. 6149

22 अक्टूबर, 1991।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-1975 में शैक्षिक सोसायटी को रियायती दरों पर पट्टे पर आवंटित भूमि-1973 के नियमों के अनुसार 1991 में भूमि किराए में पूर्वव्यापी वृद्धि का आदेश-अंतर अवशिष्ट की मांग-समीक्षा के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति में 16 साल पहले लिया गया निर्णय 1973 के नियमों के बावजूद भूमि किराया तय करना अंतिम है-भूमि किराए को उत्तराधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है।

माना जाता है कि यह सच है कि 1973 के नियमों ने लीज होल्ड के आधार पर फ्री होल्ड के आधार पर भूमि आवंटित करने की पिछली नीति को बदल दिया, लेकिन घटनाओं के पीछे के आधार को देखते हुए, रियायती दरें यानी 1973 के नियमों में उल्लिखित दरों से कम दरें स्पष्ट रूप से 1973 के नियमों की रियायत या छूट में तय की गई थीं। हम संभवतः प्रशासन की इस अभिवाक् प्रतिगृहीत करना नहीं कर सकते हैं कि नियमों में रियायत या छूट देने के बजाय, यह प्रशासन द्वारा की गई गलती के कारण हुआ है। यह तथ्य कि क्या 16 साल पहले लिया गया निर्णय नियमों में ढील देकर लिया गया था या गलती से लिया गया था, हालाँकि, हमें और अधिक रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमों में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और केवल इसी आधार पर, यह याचिका सफल होने के योग्य है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, विशेष रूप से सरशियोरेराई की प्रकृति में, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए:-

- (i) मामले का लिखित अभिलेख प्रस्तुत करना;

- (ii) 1 एक डब्ल्यूआरआई जारी करने के लिए याचिकाकर्ता सोसायटी को आवंटित भूमि के लिए देय भूमि किराए को रुपये से बढ़ाने के सरशियोरराई के फैसले को रद्द करते हुए। 100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। आबंटन की तारीख से 21 जून, 1975 से पूर्वव्यापी रूप से 12,696 प्रति वर्ष, -संलग्नक पी-1 और पी-2 के माध्यम से इसे गैरकानूनी और अवैध कानून के सिद्धांत के खिलाफ घोषित करना;
- (iii) आई. आई. टी. आई. ने आगे प्रार्थना की है कि इस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान संलग्नक पी-1 और पी-2 के आदेशों के संचालन पर रोक लगाई जाए;
- (iv) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश भी जारी कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।
- (v) अग्रिम सूचना की आवश्यकता और अनुलग्नकों की सत्यापित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए छूट/वितरण का आदेश दिया जाना चाहिए;
- (vi) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता सोसायटी के पक्ष में दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विक्रान्त शर्मा के साथ अधिवक्ता जी. के. चतरथा।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव विज के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप।

न्याय

वी. के. बाली जे.

लगभग डेढ़ दशक पहले याचिकाकर्ता को 10 एकड़ भूमि के आवंटन से संबंधित आवंटन पत्र में बदलाव लाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेश और उसके बाद जारी किए गए नोटिस के बाद याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत इस रिट याचिका को दायर करके कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन इससे पहले कि जिन दो आधारों पर नोटिस और आदेश पर हमला किया गया है, उनकी आगे जांच की जाए, इस याचिका में शामिल तथ्यों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

2. चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक जनादेश के अनुसरण में चंडीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी स्कूल/कॉलेज स्थापित करने की परिकल्पना की है। चंडीगढ़ शहर उन स्थानों में से एक है जहाँ जीवन की सभी आवश्यकताओं को शुरू किया जाना था और शुरुआत से ही तैयार किया जाना था, भारी वित्तीय भागीदारी के कारण शिक्षा प्रदान करने का यह विशाल कार्य प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अपने उद्देश्य से नहीं किया जा सका, इस प्रकार, निजी व्यक्तियों और सांप्रदायिक समाजों की भागीदारी की आवश्यकता थी।

3. व्यक्तियों और समितियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, प्रशासन ने नाममात्र मूल्य पर और फ्री होल्ड के आधार पर भूमि की पेशकश की। नाममात्र मूल्य पर और फ्री होल्ड के आधार पर भूमि प्राप्त करने वालों में से कुछ स्वीकृत रूप से डी. ए. वी. पुरुष महाविद्यालय, डी. ए. वी. महिला महाविद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह पुरुष महाविद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह महिला महाविद्यालय और सेक्टर 8 में डी. ए. वी. स्कूल थे। याचिकाकर्ता-सोसायटी ने भी चंडीगढ़ में एक गैर-सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 20/25 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए प्रशासन से संपर्क किया और प्रशासन ने 5 फरवरी, 1974 के पत्र के माध्यम से सेक्टर 32-सी, चंडीगढ़ में 10 एकड़ भूमि को 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित करने की पेशकश की। 10 प्रति वर्ग गज और इसके अलावा, रुपये की दर से जमीन का किराया। 1000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। इस कारण से कि याचिकाकर्ता सोसायटी को 10.50 एकड़ के भूखंड के आवंटन का प्रस्ताव पट्टे के आधार पर था और भूमि किराए के भुगतान पर भी था, जो कि अन्य संस्थानों के मामले में अपनाया गया पाठ्यक्रम नहीं था, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, भले ही सोसाइटी के अध्यक्ष ने आवंटन को स्वीकार कर लिया हो, फिर भी उन्होंने अनुरोध किया कि कीमत को कम किया जाए क्योंकि यह अत्यधिक था और वार्षिक भूमि किराए को भी छूट दी जाए क्योंकि यह मौजूदा गैर-सरकार और इसी तरह चंडीगढ़ में रखे गए शैक्षणिक संस्थानों से नहीं लिया गया था। लीज होल्ड की प्रणाली के खिलाफ एक मजबूत याचिका भी दायर की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा उठाई गई दलीलों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया और वास्तव में उस पर जोर दिया कि वह उपरोक्त दरों पर 99 वर्षों के लिए पट्टे पर रखने के आधार पर सेक्टर 32 में प्रस्तावित भूमि के आवंटन के संबंध में सहमति दे। याचिकाकर्ता-सोसायटी को कार्रवाई में तेजी लाने और अपने प्रस्ताव के पत्र में उल्लिखित शर्तों पर आवंटन के संबंध में अपनी सहमति भेजने के लिए कहा गया था। वित्त सचिव ने 21 दिसंबर, 1974 के व्यापक पत्र में चंडीगढ़ प्रशासन के 99 वर्षों के लिए याचिकाकर्ता-सोसायटी को पट्टे पर रखने के आधार पर 10 एकड़ भूमि के टुकड़े को उसी दर पर हस्तांतरित करने के निर्णय की जानकारी दी, जो संपदा अधिकारी ने 3 अप्रैल, 1974 के पत्र में प्रस्तावित किया था। चूंकि ऊपर उल्लिखित दरों पर भूखंड प्राप्त करने के लिए सहमति

थी। याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा भी दी गई, हालांकि ऊपर उल्लिखित कुछ आपत्तियां उठाई गई थीं, एस्टेट अधिकारी ने 2 जनवरी, 1975 के व्यापक पत्र में याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले की जानकारी दी, जिसमें याचिकाकर्ता को 6 से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर सह-शैक्षिक डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए कहा गया है। एक बार फिर, उपरोक्त पत्र में, याचिकाकर्ता को उपरोक्त दरों पर पट्टे के आधार पर भूखंड के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में अपनी सहमति देने और मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विधिवत सत्यापित गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर एक वचन पत्र देने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता-सोसायटी को रुपये की राशि प्रेषित करने की आवश्यकता थी। 1,27,089 भूमि के 25 प्रतिशत प्रीमियम के कारण ताकि आवंटन पत्र जारी किया जा सके। याचिकाकर्ता-सोसायटी ने 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर 10.50 एकड़ भूमि के आवंटन को स्वीकार कर लिया। 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से जमीन के किराए के अलावा। 100 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। इसने अपने अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र भी प्रस्तुत किया। जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने 21 जून, 1975 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त नियमों और शर्तों पर आवंटन पत्र जारी किया। उपरोक्त दरों के अनुसार कुल प्रीमियम का आकलन रु। 5,08,356 और रुपये की राशि के रूप में। 1,27,089 जो प्रीमियम के 25 प्रति उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, किशतों के रूप में भुगतान की अनुसूची चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा तय की गई थी, जिसके अनुसार रु। 1,47,282 को 10 जुलाई, 1976 को जमा किया जाना था। इसी राशि की दूसरी किशत 10 जुलाई, 1977 को जमा की जानी थी, जबकि उसी राशि की तीसरी किशत 10 जुलाई, 1978 को या उससे पहले जमा की जानी थी और चालू वर्ष का वार्षिक भूमि किराया रु। 10 जुलाई, 1976 को या उससे पहले 1,050। मान लीजिए, याचिकाकर्ता सोसायटी ने लंबे समय से और नियत तारीखों पर ब्याज के साथ प्रीमियम की सभी किशतों का भुगतान किया था। इसके बाद भी, जब एस्टेट अधिकारी ने जमीन के किराए के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया, तो उसे समय पर भेज दिया गया। जब 16 वर्षों की अवधि बीत चुकी थी और उस समय तक प्रीमियम की सभी किशतों का भुगतान किया जा चुका था और सभी वर्षों के लिए भूमि किराया भी प्रेषित कर दिया गया था और जब कॉलेज की पूरी इमारत का निर्माण किया गया था और संस्थान छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में शीर्ष गियर में था, तो याचिकाकर्ता को पूरी तरह से निराशा और आश्चर्य हुआ कि प्रशासन द्वारा एस्टेट अधिकारी द्वारा से लिए गए निर्णय से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि भूमि किराया चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग्स के रूप में जाने वाले नियमों में निर्धारित दर से बढ़ाया जाएगा।

नियम 1973। उपरोक्त निर्णय से पता चलता है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 29 जनवरी, 1991 को निर्णय लिया था, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एस्टेट अधिकारी द्वारा

याचिकाकर्ता को 15 मार्च, 1991 को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता को 15 मार्च, 1991 को ही नोटिस (अनुलग्नक पी2) भी प्राप्त हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को बिना किसी अनिश्चितता के रुपये का भुगतान करने की धमकी दी गई थी। 1,74,690 अर्थात् आबंटन के मूल पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार सोसायटी द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए भूमि किराए और चंडीगढ़ लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग्स रूल्स 1973 (इसके बाद 1973 के नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत देय किराए के बीच का अंतर नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता सोसायटी को उक्त नियमों के तहत परिकल्पित भूमि किराए का भुगतान न करने के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता-सोसायटी ने कई वैध आधारों पर उपरोक्त निर्णय और नोटिस को अमान्य और अन्यायपूर्ण माना और इसलिए, इसके ऐसे विचारों के मद्देनजर, एक अभ्यावेदन करने का निर्णय लिया गया जो वास्तव में 1 अप्रैल, 1991 को किया गया था, जिसकी प्रति संलग्नक पी 10 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है। हालाँकि, जब कार्यालय में किसी ने नहीं सोचा कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और उसमें प्रस्तावित बिंदुओं पर ध्यान देने के लायक है, तो याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करके अपने रुख को सही साबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का दोहरा तर्क यह है कि प्रशासक/सचिव, जो भूमि के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी थे, ने याचिकाकर्ता को रुपये की दर से आवंटन करते समय एक सचेत और विचारशील निर्णय लिया था। 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से जमीन के किराए के अलावा। 100 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। निर्णय को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए लिए जाने के बाद, उत्तराधिकारी प्रशासक/सचिव के पास अपने पूर्ववर्ती के निर्णय की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी, विशेष रूप से जब पहला निर्णय 16 साल पहले लिया गया था, उस समय के दौरान याचिकाकर्ता इस स्तर पर पहुंच गया था कि अगर नई दरें उपयुक्त नहीं थीं, तो वह पहले ही रु। भवन के निर्माण में सात लाख। दूसरा विवाद, निश्चित रूप से, न्यायसंगत बहिष्कार की सर्वविदित याचिका है।

5. चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री आर. के. राव द्वारा दायर लिखित बयान के माध्यम से याचिका का विरोध किया है। भले ही हर बात में कोई तथ्य स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण आवंटन पत्र में पूर्वव्यापी संशोधन की आवश्यकता पड़ी और प्रशासन का निर्णय याचिकाकर्ता-सोसायटी के खिलाफ कार्यवाही की जाए यदि अवशिष्ट राशि का भुगतान नहीं किया गया था, और उक्त परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, जिनका वर्णन इसके बाद दिया जाएगा और साथ ही 1973 के नियमों

के नियम 13 में निर्धारित अधिदेश से, विवादित आदेश और नोटिस को उचित ठहराने की मांग की गई है। यह निवेदन किया जाता है कि चंडीगढ़ मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन संघ, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री एम. एल. सैनी ने राज्यसभा में एक याचिका दायर की, जिस पर सांसद श्री पवन कुमार बंसल ने विधिवत हस्ताक्षर किए। उपरोक्त याचिका के परिणामस्वरूप, वित्त सचिव और अन्य 2 जनवरी, 1988 को राज्यसभा संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए, जिसमें उप सचिव वित्त ने इच्छा व्यक्त की कि स्कूलों को भूमि आवंटन से संबंधित मामले को पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के साथ उन्हें प्रस्तुत किया जाए ताकि मामले को राज्यसभा समिति के समक्ष उचित भविष्य में प्रस्तुत किया जा सके। अधीक्षक वित्त-1 ने 5 फरवरी, 1988 को एक ध्यान दें प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि शिशु निकेतन मॉडल स्कूल, दयानंद बाल विद्यालय और मानव मंगल स्कूल को 5 करोड़ रुपये की रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी। 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर 10 रुपये प्रति वर्ग गज के दर से भूमि किराया देय है। 100 प्रति एकड़ प्रति वर्ष जो नियमों के खिलाफ था। 1973 के नियमों के नियम 13 के अनुसार, भूमि किराया प्रति 33 वर्षों में 21 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से लिया जाना था, लेकिन उक्त नियम 20 अगस्त, 1973 को अधिसूचित किए गए थे और उपरोक्त शैक्षणिक संस्थानों को भूमि के आवंटन के समय लागू थे। चूंकि उपरोक्त शैक्षणिक संस्थानों को भूमि देने का निर्णय नियमों के खिलाफ दिया गया था, इसलिए उपरोक्त संस्थानों से निर्धारित दर पर भूमि किराया लेने का निर्णय लिया गया और चूंकि याचिकाकर्ता-सोसायटी के तथ्य भी उपरोक्त संस्थानों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के समान थे, इसलिए विवादित आदेश और नोटिस जारी किए गए। लिखित बयान में की गई दलीलों और चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप द्वारा उठाई गई दलीलों से, प्रशासन की कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने का एकमात्र आधार यह है कि याचिकाकर्ता-सोसायटी को भूमि देने की रियायत जैसा कि आवंटन पत्र में बताया गया है, नियम 13 के अधिदेश के खिलाफ था और ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई कोई भी दलील सही नहीं होगी। यह तर्क दिया जाता है कि प्रशासक/वित्त सचिव का उत्तराधिकारी उस निर्णय के विपरीत निर्णय लेने के लिए सक्षम था जो पहले लिया गया था जब वह 1973 के नियमों के खिलाफ था और यह भी कि अधिनियम के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती थी।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को काफी देर तक सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का कारण सराहनीय है और इसलिए, इस याचिका को सफल होना चाहिए। 1973 के नियमों के अवलोकन, जिसके तहत भूमि का आवंटन किया गया था, में समीक्षा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। चंडीगढ़ में भूमि और भूखंडों के हस्तांतरण की शक्ति को 1952 के पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम के रूप में जाने जाने वाले अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। 1952 के अधिनियम की खंड 3 और 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए 1973 के नियम अस्तित्व में आए। श्री आनंद स्वरूप, 1952 के अधिनियम के तहत भी किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त समीक्षा की किसी भी शक्ति की ओर इशारा नहीं समर्थ हैं। यह अब कानून का अच्छी तरह से तय प्रस्ताव है कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है जब तक कि उक्त शक्ति उसे उस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है जिसके तहत वह अपनी अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। हमने ऊपर जो कहा है वह न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला से पर्याप्त रूप से बनाया गया है और यदि कोई संदर्भ आवश्यक है, तो वह आर. टी. रंगाचारी बनाम राज्य सचिव (1) और डॉ. श्रीमती से उपलब्ध है। कुरेतेश गुप्ता बनाम हिंदू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर (यू. पी.) और 'अन्य का प्रबंधन' (2)।

7. मामले के तथ्य, जैसा कि ऊपर पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे कि प्रशासन के अंत में महसूस की गई अत्यधिक आवश्यकता के मद्देनजर व्यक्तियों और समाजों को चंडीगढ़ में नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने में प्रशासन के साथ हाथ मिलाने के लिए लुभाया गया था। प्रशासन के अंत में वित्त की पर्याप्तता और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अत्यधिक आवश्यकता ने प्रशासन को रियायती दरों पर भूमि सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की पेशकश करने के लिए राजी किया। शुरुआत में, फ्री होल्ड के आधार पर कई गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को भूमि की पेशकश की गई थी, जिनसे, बेशक, कभी भी जमीन का किराया नहीं लिया गया था। यह सच है कि 1973 के नियमों ने लीज होल्ड के आधार पर फ्री होल्ड के आधार पर भूमि आवंटित करने की पिछली नीति को बदल दिया, लेकिन घटनाओं के पीछे के आधार को देखते हुए, रियायती दरें यानी 1973 के नियमों में उल्लिखित दरों को स्पष्ट रूप से 1973 के नियमों की रियायत या छूट में तय किया गया था। हम संभवतः प्रशासन की इस अभिवाक् प्रतिगृहीत करना नहीं कर सकते हैं कि नियमों में रियायत या छूट देने की जगह, यह प्रशासन द्वारा की गई गलती के कारण था। यह तथ्य कि क्या 16 साल पहले लिया गया निर्णय नियमों में ढील देकर लिया गया था या गलती से लिया गया था, हालाँकि, हमें और अधिक रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमों में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और केवल इसी आधार पर, यह याचिका सफल होने के योग्य है।

8. भले ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें न्यायसंगत रोक की प्रयोज्यता पर संबोधित किया है-लेकिन जैसा कि ऊपर देखे गए पहले बिंदु पर, हम याचिकाकर्ता को वांछित राहत देने के लिए इच्छुक हैं, हमें इस प्रश्न में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं

(1) A.I.R 1937 P.C. 27

(2) A.I.R. 1997 S.C. 2186

हैं और इसे केवल यह देखते हुए छोड़ दें कि याचिकाकर्ता के पक्ष ने "भारत संघ और अन्य बनाम एंग्लो अफगान एजेंसियां आदि" पर भरोसा किया है। (3) और मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "(4), जबकि प्रशासन की ओर से पेश वकील ने वसंत कुमार राधाकृष्णन वीरा बनाम बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल (5) पर भरोसा किया है।

9. ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका आगे बढ़ती है। आदेश संलग्नक पीएल और नोटिस संलग्नक पी2 को रद्द कर दिया जाता है और रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़, हरियाणा

